



मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय बल्लभमवन

आदेश :-

मोपाल दिनांक 28 जून 2011

कमांक एफ 2(क) 29/10/बी-3/दो राज्य शासन द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं नाननीय मुख्यमंत्री जी की सुझा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थ सुरक्षा कर्मियों को केवल वेतन (येड-पे छोड़कर) का 30 प्रतिशत की दर से विशेष वेतन निम्न शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है-

Handwritten notes: '30 JON', 'AT 6', '15/11', '14 JUL', '1102'.

1. यह विशेष वेतन केवल स्वतः दोनों प्राधिकारियों की सुझा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को देया होगा।
2. नियमित अवकाश अवधि के दौरान यह मत्ता देय नहीं होगा।
3. येड-पे रूप में 5400 या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को इसकी पात्रता नहीं होगी।
4. यदि बुद्धिस्थान में परिवर्तन होता है तो तत्काल प्रभाव से यह विशेष वेतन बंद कर दिया जाएगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओओ को 711/716/ब-8/चार/11 दिनांक 06-06-2011 द्वारा प्रदान की गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी की जाती है।

F4 J11 11/11/11 P.S. A7

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डी.क. राघवानी)
अवर सचिव

मध्य शासन गृह विभाग
मोपाल दिनांक 28 जून 2011

पृष्ठा कमांक एफ 2(क) 29/10/बी-3/दो
पंतिनिधि-

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय मोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य शासन, वित्त विभाग, मोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, खालियर
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्याप्त मवन, मोपाल
5. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल मवन, मोपाल

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials and text: 'अवर सचिव मध्य शासन गृह विभाग'.

अवर सचिव (पुलिस) विभाग (बी-4) मोपाल

परिशिष्ट - "ब"
अत्यायुक्त प्रशासन

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय



कमांक एफ2(क)29/10/बी-3/बी. भोपाल, दिनांक 25/02/2012
प्रति,

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
(सुपरवाइजर) पुलिस मुख्यालय
भोपाल, (मोप्र)

विषय:- महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की
शुभता में पदस्थ कर्मियों को स्वीकृत विशेष वेतन आदेश में
संशोधन बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक/विशा/6/पीए/2011-16/2750 दिनांक
11.7.2011. —P/1111/C

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ उक्त प्रस्ताव के बिन्दु कमांक 1 एवं 2 के संबंध में वित्त विभाग
द्वारा निम्नानुसार टीप अंकित की गई है:-

1- वित्त विभाग द्वारा वेतन पर बेंड वेतन का 30 प्रतिशत की दर से
विशेष वेतन देने की सहमति दी है। धूम्र पेंशन डीए आदि की गणना में ग्रेड पे
शागिल किया जाता है अतः प्रस्तावानुसार विशेष वेतन की गणना हेतु मूल वेतन
में ग्रेड पे शामिल करने की सहमति प्रदान की जाती है।

2- विशेष गत्ते संबंधित कर्मचारी के नियमित कार्य करने के दौरान ही
दिये जाते हैं। नियमित अवकाश से आशय EL, HPL, Commuted Leave, EOL, Leave
Not Due है। सी.एल. एवं अन्य शाराकीय अवकाश में इसकी पात्रता रहेगी।

3- गत्ते का नाम परिवर्तित करने से यदि अन्य कोई दायित्व उत्पन्न
नहीं होते हैं तो बिन्दु कमांक- 4 के प्रस्ताव अनुसार इसे संशोधित कर
जोखिम गत्ता नागित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। यह सहमति
वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक- 1291/1149/बी-8/चार/11/ दि
19/12/ के परिप्रेक्ष्य में प्रदान की जाती है।

सत्य-प्रतिलिपि

उप पुलिस अधीक्षक (विधि)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

(आरोनी वैष्णव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(वि-1)